

योगी सरकार का किसानों एवं गरीब परिवारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय,
खाद्यान्न खरीद नीतियों और उज्ज्वला योजना सहित चार महत्वपूर्ण
प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

धान खरीद के लिए 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य, प्रदेश में लगभग
4,500 क्रय केंद्रों के माध्यम से होगी खरीद

सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 2,441 तथा ग्रेड—ए धान का
रु0 2,461 प्रति कुंतल निर्धारित

मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद 31 दिसंबर तक, प्रदेश में 455 क्रय
केंद्रों के माध्यम से किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ
मोटे अनाजों की कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य, पारदर्शिता
के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन की व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशकृकिसानों को 48 घंटे के भीतर
किया जाए भुगतान, बिचौलियों की भूमिका पर प्रभावी अंकुश

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी
सिलेंडर रिफिल का लाभ, लगभग रु0 2,142.78 करोड़ का अनुमानित व्यय
खाद्यान्न खरीद एवं सीएमआर के लिए 85 हजार गांठ जूट बोरो की खरीद
पर लगभग रु0 625.71 करोड़ के व्यय को मंजूरी

किसानों की खुशहाली, उनकी मेहनत का उचित मूल्य और गरीब परिवारों
का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता—खाद्य एवं रसद मंत्री श्री
मनोज कुमार पाण्डेय

लखनऊ : 09 अक्टूबर, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक
समृद्धि, खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने तथा गरीब एवं
जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026—27 की धान खरीद नीति, मक्का, बाजरा एवं ज्वार
की खरीद नीति, खाद्यान्न खरीद एवं सीएमआर हेतु जूट बोरो की खरीद तथा प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल
उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने इन निर्णयों को किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं गरीब परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, खरीद प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धान खरीद के लिए 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य, लगभग 4,500 क्रय केंद्रों पर होगी खरीद

मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीद नीति के अंतर्गत प्रदेश में 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए लगभग 4,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 2,441 प्रति कुंतल तथा ग्रेड-ए धान का रु0 2,461 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 15 अक्टूबर, 2026 से 15 फरवरी, 2027 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक की जाएगी।

क्रय केंद्रों का निर्धारण किसानों की सुविधा, क्षेत्रीय उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा क्रय केंद्रों की स्थापना एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश-किसानों को 48 घंटे के भीतर मिले भुगतान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न का भुगतान 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए। किसानों को उनकी उपज का मूल्य सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में उपलब्ध कराया जाएगा। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। धान खरीद में एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत फार्मर आईडी तथा ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था अपनाई जाएगी। धान के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग किया जाएगा। चयनित जनपदों में सीएमआर हेतु जूट बोरों की क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग एवं बिलिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

खाद्य एवं रसद मंत्री ने कहा कि किसानों को समय से भुगतान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। खरीद व्यवस्था में अनावश्यक विलंब अथवा किसानों को असुविधा पहुंचाने वाली स्थितियों को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

श्रीअन्न उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात, 31 दिसंबर तक होगी मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद

मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में श्रीअन्न अर्थात् मोटे अनाजों की खरीद नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत मक्का, बाजरा एवं ज्वार की सरकारी खरीद 31 दिसंबर, 2026 तक की जाएगी।

मोटे अनाजों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैं—

ज्वार (मालदांडी)— रु0 4,073 प्रति कुंतल

ज्वार (हाइब्रिड)— रु0 4,023 प्रति कुंतल

बाजरा— रु0 2,900 प्रति कुंतल

मक्का— रु0 2,410 प्रति कुंतल

प्रदेश में बाजरा की 2.20 लाख मीट्रिक टन, ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन तथा मक्का की 15 हजार मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन फसलों की खरीद के लिए कुल 455 क्रय केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इनमें बाजरा के 300, ज्वार के 80 तथा मक्का के 75 क्रय केंद्र शामिल हैं।

मक्का की खरीद 25 जनपदों में

मक्का की खरीद बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, गोंडा, देवरिया, बलिया, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र एवं ललितपुर में की जाएगी। इन जनपदों में 75 क्रय केंद्रों के माध्यम से 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

बाजरा की खरीद 33 जनपदों में

बाजरा की खरीद बुलंदशहर, रामपुर, संभल, अमरोहा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट एवं हमीरपुर में की जाएगी। इन 33 जनपदों में 300 क्रय केंद्रों के माध्यम से 2.20 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ज्वार की खरीद 13 जनपदों में

ज्वार की खरीद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर, जालौन, झांसी एवं फिरोजाबाद में की जाएगी। इन जनपदों में 80 क्रय केंद्रों के माध्यम से 50 हजार मीट्रिक टन ज्वार खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

ई-पॉप उपकरणों से होगी खरीद, बिचौलियों पर लगेगा अंकुश

मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज) उपकरणों के माध्यम से किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। किसानों को भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-0150 उपलब्ध है। किसान आवश्यकता पड़ने पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अथवा विपणन निरीक्षक से भी संपर्क कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसानों से खरीद सुनिश्चित करना, बिचौलियों की भूमिका पर अंकुश लगाना तथा सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाना है।

खाद्यान्न खरीद एवं सीएमआर के लिए 85 हजार गांठ जूट बोरो की खरीद को मंजूरी

मंत्रिपरिषद् द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद, सीएमआर सम्प्रदान तथा मोटे अनाजों की खरीद के लिए 85 हजार गांठ जूट बोरो की खरीद संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन बोरो की खरीद जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से की जाएगी। प्रति गांठ ₹ 73,613.06 की दर के आधार पर कुल लगभग ₹ 625.71 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस निर्णय से खाद्यान्न खरीद, भंडारण एवं परिवहन के लिए आवश्यक बोरो की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी तथा क्रय व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा।

उज्ज्वला लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल, गरीब परिवारों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

योजना के अंतर्गत प्रथम चरण अक्टूबर से दिसंबर, 2026 तथा द्वितीय चरण जनवरी से मार्च, 2027 तक संचालित किया जाएगा। दोनों चरणों में पात्र लाभार्थियों को एक-एक निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लगभग ₹0 2,142.78 करोड़ का व्यय अनुमानित है। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता के अनुसार आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करने वाले तथा आधार से जुड़े बैंक खाताधारक उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घरेलू खर्च में राहत मिलने के साथ ही स्वच्छ रसोई ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याण सरकार का मूल संकल्प—खाद्य एवं रसद मंत्री

खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसान हितों की रक्षा एवं गरीब कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का उचित मूल्य दिलाना, खरीद केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, समय से भुगतान सुनिश्चित करना तथा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मंत्री ने कहा कि धान सहित मोटे अनाजों की सरकारी खरीद से किसानों को अपनी उपज बेचने के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने का निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी, डिजिटल तकनीक का उपयोग तथा किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का संकल्प है कि अन्नदाता की मेहनत को सम्मान मिले, उसकी उपज का उचित मूल्य समय से प्राप्त हो तथा प्रत्येक पात्र गरीब परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

सम्पर्क सूत्र— अखिलेश पाण्डेय

राघवेन्द्र / 03:45 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upsoochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in